



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 04 चैत्र, शक संवत्, 1933

(दिनांक : 25 मार्च, 2011)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")।
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख" तथा "ग")।
3. निधन के निदेश।
4. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-23(4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2001-2002 से वित्तीय वर्ष 2006-2007 तक के वार्षिक लेखों का विवरण तथा वार्षिक आर्थिक चिट्ठे सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. सभापति, अनुसूचित जाति जन जाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की अनुसूचित जाति जन जाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति (2009-10) का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
7. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
8. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
9. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
10. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"घ")
11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
12. श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैण) घोषित की जाय”

(मुद्रित प्रतियां बाद में
वितरित की जायेंगी)

13. श्री अजय टम्टा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्न संकल्प पर चर्चा जारी :-

“यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तथा प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गंभीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछखाली, मझोड़, जालली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।”

14. निम्नलिखित संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

1. श्री हरभजन सिंह चीमा “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जाय।”
2. श्री जोत सिंह गुनसोला “इस सदन का सुविचारित मत है कि नवगठित राज्य उत्तराखण्ड में लोकतंत्र की सुदृढ़ स्थापना तथा प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्था के योगदान को प्रभावी बनाने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा विधान भवन निर्माण हेतु किये गये 88 करोड़ के बजट प्राविधान का सदुपयोग कर निर्धारित समयावधि में विधान भवन निर्माण की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जाय।”

15. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।”

16. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाएं।”

17. डा० हरक सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।”

18. निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

1. श्री जोत सिंह गुनसोला

“इस सदन का सुविचारित मत है कि संविधान 74 वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।”

2. काजी निजामुद्दीन

“इस सदन का सुविचारित मत है कि - “राज्य में आम आदमी को मंहगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पेट्रोल पर वैट को घटाया जाये।”

19. वित्तीय वर्ष 2011-2012 के आय-व्यय की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) उद्योग मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रुपये 893437 हजार (रुपये नवासी करोड़ चौतीस लाख सैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(2) परिवहन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रुपये 1752094 हजार (रुपये एक सौ पच्चहत्तर करोड़ बीस लाख चौरानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(3) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18, सहकारिता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रुपये 399316 हजार (रुपये उन्तालीस करोड़ तिरानवे लाख सोलह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(4) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये **रुपये 7479707 हजार (रुपये सात सौ सैंतालीस करोड़ सतानवे लाख सात हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(5) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 5780322 हजार (रुपये पांच सौ अड़हत्तर करोड़ तीन लाख बाईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(6) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 8731699 हजार (रुपये आठ सौ तिहत्तर करोड़ सोलह लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(7) समाज कल्याण मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 2277112 हजार (रुपये दो सौ सत्ताईस करोड़ इक्कहत्तर लाख बारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(8) पेयजल मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 7284387 हजार (रुपये सात सौ अठ्ठाईस करोड़ तैंतालीस लाख सत्तासी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(9) श्रम मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 845196 हजार (रुपये चौरासी करोड़ इक्कावन लाख छियानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(10) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 332173 हजार (रुपये तैंतीस करोड़ इक्कीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

(11) राजस्व मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 8936314 हजार (रुपये आठ सौ तिरानवे करोड़ तिरसठ लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

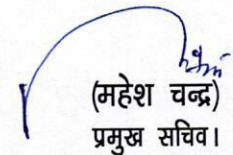
(12) खाद्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये रुपये 3311899 हजार (रुपये तीन सौ इक्तीस करोड़ अठ्ठारह लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ड))

19. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।
20. जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2003 में सिंगली से बस्तड़ी तक 2.5 कि०मी० मार्ग स्वीकृत होने के पश्चात भी निर्माण हेतु द्वितीय फेज की धनराशि न आने से जनता में उत्पन्न रोष के संबंध में श्री विशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।
21. जनपद हरिद्वार में बी०पी०एल० परिवारों को बिजली देने के लिए लगाये गये ट्रांसफार्मरों के फुंक जाने पर न बदले जाने के संबंध में हाजी तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2011 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य।

देहरादून :
दिनांक : 25 मार्च, 2011

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।

नत्थी "घ"

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 2011 की बैठक में दिनांक 25 मार्च, 2011 तक के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:-

मार्च, 2011

25 शुक्रवार असरकारी दिवस (आधा दिन)

असरकारी संकल्प

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड प्रदेश की राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैण) घोषित की जाय"

2. श्री अजय टम्टा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा जारी :-

"यह माननीय सदन प्रबल सिफारिश करता है कि प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत तथा प्रशासनिक दृष्टि से जन सामान्य को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में वर्तमान विकास खण्डों की संख्या को बढ़ाते हुए नए विकास खण्डों के सृजन पर गंभीरता से विचार किया जाय, विशेषकर जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत मछवाली, मझोड़, जालली, सोमेश्वर नये विकास खण्ड बनाये जाने तथा प्रदेश में लगभग 30 नये विकास खण्डों का निर्माण किए जाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय।"

3. निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

- (1) श्री हरभजन सिंह चीमा "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का पुर्नगठन किया जाय।"

- (2) श्री जोत सिंह गुनसोला "इस सदन का सुविचारित मत है कि नवगठित राज्य उत्तराखण्ड में लोकतंत्र की सुदृढ़ स्थापना तथा प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की सर्वोच्च संस्था के योगदान को प्रभावी बनाने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा विधान भवन निर्माण हेतु किये गये 88 करोड़ के बजट प्राविधान का सदुपयोग कर निर्धारित समयावधि में विधान भवन निर्माण की कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ की जाय।"

नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव -

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर से जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चौखुटिया तक रेलवे लाईन बिछाई जाय ताकि उक्त सुदूर क्षेत्रों का समग्र विकास हो सके।"

2. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

"प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आधुनिक पर्यटन के नये आयाम तलाशे जाएं।"

3. डा0 हरक सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।”

4. निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा -

(1) श्री जोत सिंह गुनसोला, “इस सदन का सुविचारित मत है कि संविधान 74 वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।”

(2) काजी निजामुद्दीन, “इस सदन का सुविचारित मत है कि - “राज्य में आम आदमी को मंहगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पेट्रोल पर वैट को घटाया जाये।”

(आधा दिन)

निम्नलिखित अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण चर्चा एवं मतदान:-

अनुदान संख्या 1-23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
2-24	परिवहन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
3-18	सहकारिता विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
1-20	सिंचाई, एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की अनुदान, पर मांग, चर्चा और मतदान।
2-15	कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
3-30	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
4-31	ट्रायबल प्लान से संबंधित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
1-13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
2-16	श्रम रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
3-05	निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
1-06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
2-25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

नत्थी 'ड'

वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या:- 23 उद्योग, 24 परिवहन, 18 सहकारिता, 20 सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण, 15 कल्याण योजनायें, 30 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 31 ट्रायबल प्लान, 13 जलापूर्ति, 16 श्रम, 05 निर्वाचन, 06 राजस्व, 25 खाद्य विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
क- 1. डा0 हरक सिंह रावत, 2. श्री यशपाल आर्य, 3. श्री प्रीतम सिंह, 4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा, 5. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, 6. श्रीमती अमृता रावत, 7. श्री दिनेश अग्रवाल, 8. श्री जोत सिंह गुनसोला, 9. श्री रणजीत सिंह रावत, 10. श्री तिलक राज बेहड़, 11. श्री बलवीर सिंह नेगी, 12. श्री गोपाल सिंह राणा, 13. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" 14. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, 15. श्री केदार सिंह रावत, 16. श्री राजेश जुवांठा, 17. श्री करन माहरा, 18. श्री मनोज तिवारी, 19. श्री मयूर महर,	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।
ख- 1. मौ0 शहजाद, 2. श्री सुरेन्द्र राकेश, 3. श्री हरिदास, 4. हाजी तसलीम अहमद,	-तदैव-
ग- 1. काजी निजामुद्दीन, 2. चौ0 यशवीर सिंह	-तदैव-
घ- 1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी	-तदैव-



प्रथम सत्र, 2011
का प्रथम शुक्रवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
शुक्रवार, 4 चैत्र, शक संवत्, 1933
(दिनांक : 25 मार्च, 2011)

नत्थी "क"

अल्पसूचित प्रश्न

काजी निजामुद्दीन
01.03.2011

** क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि राज्य के जनपद हरिद्वार में स्थापित उद्योगों द्वारा गन्दा पानी आस-पास के नाले और नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है? क्या यह सत्य है कि इसका प्रतिकूल प्रभाव जनमानस के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है? यदि हां, तो सरकार उद्योगों से निकलने वाले गन्दे पानी को प्रदूषण मुक्त किए जाने हेतु क्या उपाय कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यावरण

नत्थी "ख"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत
प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
27.01.2010

*1. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड परीक्षाओं गणित जैसे विषयों में प्रयोगात्मक एवं लिखित परीक्षा में अलग-अलग उत्तीर्ण होने को आवश्यक करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

नत्थी "ग"

तारांकित प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय 18.11.2010	*1. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू किया गया है? यदि हां, तो कब से तथा क्या विद्यालयों में तदनुसार सुविधायें भी उपलब्ध करायी गयी हैं?	शिक्षा
श्रीमती अमृता रावत 23.11.2010	*2. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कक्षा एक से बारहवी तक की शिक्षा व्यवस्था का राजकीकरण/एकीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? क्या यह सत्य है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जा चुकी है? यदि हां, तो माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के एकीकरण किए जाने के बाद बेसिक शिक्षा के लिए अलग निदेशालय की स्थापना किये जाने का क्या औचित्य है तथा इस निदेशालय की स्थापना और उसके संचालन पर कितना अतिरिक्त व्यय भार बढ़ेगा?	शिक्षा
श्री शेर सिंह गढ़िया 01.12.2010 श्री प्रीतम सिंह 02.02.2011	*3. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत कुल कितनी फेज तक के सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है? क्या यह सत्य है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से चयनित कुछ बसावटें तथा ग्राम पंचायतें अवशेष हैं? यदि हां, तो कुल कितनी बसावटें तथा ग्राम पंचायतें अवशेष है तथा इसका क्या कारण है?	ग्राम्य विकास
श्री शेर सिंह गढ़िया 03.12.2010	*4. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निर्माणाधीन सड़कों की वर्तमान प्रगति क्या है? क्या यह सत्य है कि कई सड़कों के निर्माण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? क्या सरकार उक्त निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	ग्राम्य विकास
श्री जोत सिंह गुनसोला 06.12.2010	*5. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अनिवार्य शिक्षा कानून के अन्तर्गत प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में कुल कितने गरीब विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

- श्री जोत सिंह गुनसोला 07.12.2010 *6. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि वर्तमान में सरकार के द्वारा एकल शिक्षा पद्धति का निर्णय लिया गया है? क्या सी0बी0एस0ई0 के पाठ्यक्रमों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को इस पद्धति के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने माह का प्रशिक्षण दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक? शिक्षा
- श्रीमती अमृता रावत 13.12.2010 *7. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु कोई नीति/नियमावली तैयार की गई है? यदि नहीं, तो विगत तीन वर्षों में शिक्षकों के स्थानान्तरण किस नीति/नियमावली के आधार पर किये गये हैं? क्या यह भी सत्य है कि शिक्षकों के स्थानान्तरण मध्य सत्र में बिना किसी नीति/नियमावली के ही किये जा रहे हैं और दुर्गम क्षेत्रों से सुगम क्षेत्रों में स्थानान्तरित शिक्षकों के रिक्त स्थानों पर प्रतिस्थानी नियुक्त नहीं किये गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मध्य सत्र में शिक्षकों के स्थानान्तरण का क्या मापदण्ड है और इन स्थानान्तरणों से प्रभावित शिक्षण व्यवस्था के प्रति कौन उत्तरदायी है? शिक्षा
- डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल 10.01.2011 *8. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आर्थिक सर्वे के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे कुल कितने परिवार हैं? इनमें से कितने परिवारों को बी0पी0एल0 एवं अन्तोदय राशन कार्ड उपलब्ध है? द्वितीय बुधवार के तारांकित 8 में स्थानान्तरण
- श्री मनोज तिवारी 12.01.2011 *9. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में विभाग द्वारा कितने मेलों का आयोजन किया गया? प्रत्येक मेले हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? क्या धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु कोई दिशा-निर्देश या मानक निर्धारित किये गये हैं? संस्कृति
- श्री मयूख महर 06.12.2010 *10. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में केन्द्र सरकार द्वारा बी0ए0डी0पी0 के कार्यों को निविदा के माध्यम से कराये जाने के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्र 129/33 बी0ए0डी0पी0/2005-06 दिनांक 29.05.2006 द्वारा सम्बन्धित वि०ख० धारचूला, मुनस्यारी, मूनाकोट, कनालीछीना के बी०डी०ओ० को किस आधार पर 2 लाख के कार्य बिना निविदा के सम्पादित करने का अधिकार दिया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा पुनः अपने पत्रांक 1187/33 बी०ए०डी०पी०/2009-10 दिनांक 17 जुलाई, 2009 के द्वारा सिर्फ एक विकास खण्ड कनालीछीना को किस आधार पर 5 लाख तक के कार्य बिना निविदा करने का आदेश दिया गया है जबकि अन्य सम्बन्धित तीन विकास खण्ड को यह सुविधा नहीं दी गयी है? क्या सरकार बिना निविदा कार्य कर केन्द्र सरकार के निर्देशों का खुला उल्लंघन करने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो क्या ओर कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? ग्राम्य विकास

श्री किशोर उपाध्याय

15.02.2011

श्री जोत सिंह गुनसोला

01.03.2011

*11. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 15.02.2011 तक जनपदवार कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है? क्या सरकार उपरोक्त योजना में दैनिक मजदूरी बढ़ाकर रुपये 200.00 (रुपये दो सौ मात्र) करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री गणेश जोशी

28.02.2011

*12. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य गठन के उपरान्त प्रदेश में लगभग 35 राजकीय महाविद्यालय खोले गये, किन्तु देहरादून जिला मुख्यालय में एक भी राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं किया गया? क्या यह भी सत्य है कि जिला मुख्यालय में स्थित अशासकीय महाविद्यालय डी०ए०वी० (पी०जी०) कालेज में छात्र-छात्राओं की संख्या उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की तुलना में कई गुना अधिक है, जिससे महाविद्यालय प्रशासन को इतने अधिक संख्या बल को नियंत्रित करना सम्भव नहीं हो रहा है? क्या यह भी सत्य है कि सभी अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में कक्षाओं में प्रवेश संख्या यू०जी०सी० के मानकों से अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या का दबाव कम करने के लिए जनपद मुख्यालय में एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने पर विचार करेगी?

उच्च शिक्षा

श्रीमती अमृता रावत

08.12.2010

*13. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 'स्पर्श गंगा' कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा तथा उद्देश्य क्या है तथा इस कार्यक्रम के संचालन हेतु किन-किन स्रोतों से कितनी-कितनी धनराशि दान/अनुदान एवं सहायतार्थ कब-कब प्राप्त हुई है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अब तक किस-किस प्रयोजन पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा इस कार्यक्रम का संचालन कब तक चलाया जायेगा और इस कार्यक्रम के लिए होने वाली आय तथा व्यय का अनुमानित बजट क्या है?

संस्कृति

अतारांकित प्रश्न

श्री किशोर उपाध्याय

15.11.2010

1. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थापना हेतु सरकार ने नीति का निर्धारण किया है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत

15.11.2010

2. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा संख्या 107/2010 दिनांक 24.05.2010 को विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत जनता इण्टर कालेज मोटाढाक में विज्ञान के प्रवक्ता के पद सृजित करने व क्रीडा एवं विज्ञान उपकरण हेतु रु० 5 लाख (पांच लाख) दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय हेतु प्रवक्ता के पद को भरने व क्रीडा उपकरणों हेतु 5 लाख रुपये सम्बन्धित विभाग को शीघ्र अवमुक्त करायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 15.11.2010	3. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत कोटद्वार शहर की जनसंख्या में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत सरकार कोटद्वार में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	उच्च शिक्षा
काजी निजामुद्दीन 23.11.2010	4. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य में उर्दू सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्य योजना बना रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
काजी निजामुद्दीन 23.11.2010	5. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राज्य में उर्दू शिक्षा मित्रों के 263 पद वर्ष 2006 से रिक्त हैं? यदि हां, तो कब तक उक्त पदों पर नियुक्तियों कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 23.11.2010	6. क्या संस्कृति मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोटद्वार में धन आवंटन के अभाव में स्वीकृत प्रेक्षागृह लगभग 3 वर्षों से अर्द्धनिर्मित अवस्था में हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु धनावंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	संस्कृति
श्रीमती अमृता रावत 26.11.2010	7. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के ऐसे कौन से जनपद हैं जिनमें मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी नियुक्त/कार्यरत नहीं है तथा प्रश्नगत रिक्तियां कब से चली आ रही हैं? इन रिक्तियों को भरने की दिशा में शासन/सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की तैनाती सुनिश्चित की जायेगी?	ग्राम्य विकास
श्री मयूख महर 29.11.2010	8. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जू0हा0 के प्रान्तीकरण तथा उच्चीकरण करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि हां, तो अभी तक प्रदेश में किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कुल कितने विद्यालयों का उच्चीकरण एवं प्रान्तीकरण किया जा चुका है? क्या सरकार इस क्रम में विधान सभा क्षेत्र कनालीछीना के जू0हा0 स्कूल हरड़ीखान तथा तामाखानी को उच्चीकृत किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा
श्री शेर सिंह गढ़िया 30.11.2010	9. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने माध्यमिक तथा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन हैं तथा वर्तमान में उनके संचालन की क्या स्थिति है? क्या सरकार शिक्षक विहीन विद्यालयों में तत्काल शिक्षको की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शिक्षा

श्री मयूख महर
30.11.2010

10. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा वार कितने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज है तथा इन विद्यालयों में प्रत्येक में मानक के अनुसार कितने अध्यापकों की नियुक्ति का प्राविधान हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद में कुल कितने ऐसे विद्यालय है जिनमें मानकों के अनुरूप शिक्षक तथा स्थायी प्रधानाचार्य नियुक्त है और कितनों में नहीं? क्या सरकार उन विद्यालयों में शिक्षक प्रधानाचार्य नियुक्त करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री मयूख महर
30.11.2010

11. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम चैंसर के लिये बन रहे मोटर मार्ग के प्रारम्भ के भाग में जो कि 300 मीटर सैन्य क्षेत्र में आता है को सेना द्वारा निर्माण कार्य को रोक दिया गया है? यदि हां, तो उक्त गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु विभाग द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और उक्त ग्राम को कब तक मोटर सुविधा उपलब्ध हो जायेगी?

ग्राम्य विकास

श्री मयूख महर
30.11.2010

12. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के मैदानी जिले उधमसिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून में कुल कितने हाईस्कूल तथा इ0 का0 है? क्या इनमें निर्धारित मानकों से अधिक शिक्षक तैनात हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राज्य निर्माण से अब तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के 10 जनपदों से मैदानी क्षेत्र के तीन जिलों में कुल कितने अध्यापक स्थानान्तरित होकर आये हैं? क्या पर्वतीय क्षेत्र से स्थानान्तरण के समय इनके प्रतिस्थानी की व्यवस्था की गयी थी? यदि हां, तो किन-किन स्थानों में? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री मयूख महर
02.12.2010

13. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में हाईस्कूल/इ0का0 में प्रधानाचार्य के अधिकांश पद रिक्त है? क्या सरकार वर्ष 1999 के उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को जो कि प्रवक्ता पद के उच्चतम वेतनमान को प्राप्त कर चुके हैं, को उक्त रिक्त पदों पर नियुक्त करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री मयूख महर
07.12.2010

14. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के द्वितीय शुक्रवार हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 के उत्तर के सन्दर्भ में अवगत कराया गया था कि प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों को सवित्तीय मान्यता दिये जाने हेतु नीति बनाने की कार्यवाही शासन स्तर पर गतिमान है? क्या उक्त नीति शासन द्वारा बना ली गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो नीति निर्धारण में शासन द्वारा कितना समय लगेगा? क्या सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री की दिनांक 20.04.2006 की घोषणा को क्रियान्वयन करने हेतु एल0डब्लू0एस0 कन्या इण्टर कालेज भाटकोट को इण्टर वैज्ञानिक अतिरिक्त वर्ग की सवित्तीय मान्यता देने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री जोत सिंह गुनसोला
08.12.2010

15. क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 तक बाल कल्याण योजना के अन्तर्गत कुल कितने लाभार्थियों को किस-किस योजना के अन्तर्गत कुल कितने धन का लाभ पहुंचाया गया? क्या सरकार बाल कल्याण के लाभार्थियों को मिलने वाले बाल कल्याण कोष में वृद्धि पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब व कितनी? यदि नहीं, तो क्यों?

बाल विकास एवं
महिला
सशक्तिकरण

श्री मयूख महर
09.12.2010

16. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या- 1 के उत्तर के सन्दर्भ में सचिव ग्राम्य विकास के अ0शा0 पं0सं0 149/10/ए0क्यू0 64 2009 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड कनालीछीना व विकास खण्ड मूनाकोट में वी0ए0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जा रहे कार्यों की सूची के चयन में गाइड लाइन के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा कार्य स्थलों की दूरी में हेर फेर कर व्यक्ति विशेष/ग्राम विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है तथा गाइड लाइन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुये कार्यों की निविदायें नहीं लगायी गयी है? क्या मंत्री जी इसकी जांच कर दोषियों पर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री मयूख महर
09.12.2010

17. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 2009 के प्रथम शुक्रवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के सन्दर्भ में अवगत कराया गया था कि गत दो वर्षों में प्रदेश के 70 विधान सभा क्षेत्र में पूर्व मा0 वि0 302 तथा मा0 वि0 119 को उच्चीकृत किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा वार उच्चीकृत विद्यालयों के नाम की सूची उपलब्ध करायेंगे? यदि नहीं, तो क्या सरकार गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर दायित्व निर्धारित कर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री मयूख महर
13.12.2010

18. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग के सेवा नियमों के अनुसार शिक्षक बिना वेतन लिये कितना अधिकतम अवकाश ले सकता है? जनपद पिथौरागढ़ में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो इस नियम का लाभ उठा रहे हैं व कितने वर्षों से अभी तक अवकाश में हैं? क्या विभाग ऐसे अध्यापकों के पदों को रिक्त रखता है, या उनके स्थान पर प्रतिस्थानी की नियुक्ति की जाती है? यदि हां, तो क्या पिथौरागढ़ में अवकाश में रह रहे अध्यापकों के प्रतिस्थानी विद्यालयों में नियुक्त किये गये हैं? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

शिक्षा

श्री मयूख महर
13.12.2010

19. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र वार इण्टर कालेजों में कितने किन-किन विषयों के पद खाली हैं? क्या वर्तमान प्रोन्नति सूची में उक्त रिक्त स्थानों को भरने का प्राविधान रखा गया है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 31 अगस्त, 2010 तक किस-किस इण्टर कालेज में कितने लैक्चरर की नियुक्ति की गयी (नाम व विषय सहित) विवरण उपलब्ध करायेंगे तथा कितने अध्यापकों ने कार्यभार ग्रहण किया? क्या सरकार कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापकों पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री जोत सिंह गुनसोला
14.12.2011

20. क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश की लोक संस्कृति की विरासत को किस प्रकार से संजोने का कार्य किया गया? क्या सरकार प्रत्येक जनपद में संस्कृति अकादमी स्थापित करने जा रही है जिससे संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन पर कार्य किया जा सकें? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

संस्कृति

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
15.12.2010

21. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के लक्सर स्थित के0वी0 इण्टर कालेज की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल विगत 14 वर्ष पूर्व, दिनांक 06.08.1996 को समाप्त हो गया है? क्या शिक्षा मंत्री यह भी अवगत हैं कि उक्त विद्यालय में गन्ना समिति के सचिव को "प्रबन्धक" तथा एस0डी0एम0 लक्सर को "अध्यक्ष" नियुक्त किया गया है? क्या सरकार उक्त विद्यालय कार्यकारिणी के "सदस्यों" द्वारा प्रबन्ध समिति के चुनाव कराएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्रीमती अमृता रावत
15.12.2010

22. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र वीरोंखाल के अन्तर्गत विकास खण्ड एकेश्वर, पोखड। तथा वीरोंखाल से विगत तीन वर्षों में खण्ड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण कितने-कितने समय के अन्तराल में किया गया है तथा अल्पावधि में खण्ड विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण किये जाने का कारण तथा औचित्य क्या है? उक्त स्थानान्तरण किस-किस की संस्तुति अथवा शिकायत पर किये गये हैं?

ग्राम्य विकास

श्रीमती अमृता रावत
15.12.2010

23. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता तथा सहायक अध्यापकों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त चले आ रहे हैं तथा इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां न किये जाने के कारण क्या हैं? क्या यह सत्य है कि अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर दिनांक 27/05/2007 से रोक लगा दी है? यदि हां, तो नियुक्तियों पर रोक लगाये जाने के कारण क्या है तथा कब तक इन नियुक्तियों पर लगी रोक हटा ली जायेगी?

शिक्षा

- कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' 24. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या शिक्षा मंत्री यह भी स्पष्ट करेंगे कि प्रदेश में उर्दू पैरा टीचर तथा उर्दू सहायक अध्यापक के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार लोकहित में उक्त रिक्त पदों पर शीघ्र उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- श्रीमती अमृता रावत 25. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 तक राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं स्वीकृत मोटर मार्गों के नाम, लम्बाई, स्वीकृत वर्ष तथा स्वीकृत धनराशि का मार्ग एवं जनपदवार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसे मार्गों का जनपदवार विवरण क्या है जो स्वीकृति हेतु लम्बित है?
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 26. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज गैरखेत विज्ञान वर्ग हेतु स्वीकृत है? क्या उक्त कालेज में नियमित रूप से विज्ञान की कक्षाएँ कक्षा 11, एवं 12 में संचालित की जा रही हैं? यदि हां, तो वर्तमान में कितने छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं एवं कितने प्रवक्ता हैं? यदि नहीं, तो क्यों?
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 27. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये स्थान-स्थान पर स्वयं धन एकत्र कर अपने संसाधनों से अशासकीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, जो लम्बे समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में अनेक अशासकीय विद्यालयों में जहाँ शिक्षकों का अभाव है वहीं उनके भवनों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है क्या यह सत्य है कि विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैण के अन्तर्गत जनता इण्टर कालेज बाजन, आनन्द मा०वि० डुंगरी हरलाल वर्मा उ०मा० विद्यालय भाकुड़ा, इ०का० नैलगांव, मझोण, नव ज्योती, सिनार, विनायक, कृषि इ०का० चमोली, नैल सल्ट, आर्य इ०का० देघाट उ०मा०वि० वल्मरा आदि अशासकीय विद्यालयों से शिक्षकों के अभाव के साथ ही भवनों की स्थिति भी अत्यन्त जर्जर है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में अध्यापकों एवं भवनों की स्थिति में सुधार करेगी? क्या सरकार उक्त विद्यालयों को शासकीय सहायता देने के साथ-साथ प्रान्तीयकरण किये जाने पर भी विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- श्री प्रेमानन्द महाजन 28. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला ऊधमसिंह नगर में कितने राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त हैं? क्या रा०इ०का० हरिपुरा हरसान, बाजपुर में प्रधानाचार्य का पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किस नियम के आधार पर प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार वर्तमान प्रधानाचार्य को दिया गया है?

शिक्षा

ग्राम्य विकास

शिक्षा

शिक्षा

शिक्षा

श्री प्रेमानन्द महाजन
31.12.2010

29. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में किन-किन विद्यालयों में बंगला भाषा पढ़ाने की व्यवस्था है? क्या बंगाली छात्र बाहुल्य विद्यालयों में बंगला भाषा पढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31.12.2010

30. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय महाविद्यालय लक्सर (जनपद हरिद्वार) विगत 9 वर्षों से चिकित्सालय के जर्जर कक्षों में चल रहा है? क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा रु0 2.50 करोड़ की धनराशि अवस्थापना एवम् अन्य कार्य हेतु गत 2 वर्ष पूर्व स्वीकृत हो जाने के उपरान्त भी उक्त निर्माण कार्य हेतु चयनित भू-खण्ड के प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इस अत्यन्त-पिछड़े खादर क्षेत्र के एकमात्र उच्च-शिक्षण संस्थान हेतु भूमि की नौयियत परिवर्तित कर अपेक्षाकृत धनराशि स्वीकृत कर, अविलम्ब भवन आदि अवस्थापना कार्य प्रारम्भ करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31.12.2010

31. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार तहसील लक्सर स्थित ग्राम चन्द्रपुरी कला के जूनियर हाई स्कूल का उच्चीकरण वर्ष 2007 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में हुआ था? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि हाई स्कूल कक्षाओं के तीन सफल सत्रों के उपरान्त भी उक्त विद्यालय को इण्टरमीडिएट में उच्चीकृत नहीं किया गया है? क्या सरकार आगामी सत्र से पूर्व उक्त विद्यालय को उच्चीकृत करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री मनोज तिवारी
07.01.2011

32. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कुल कितने जूनियर हाईस्कूलों का उच्चीकरण हुआ है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन जूनियर हाईस्कूलों का उच्चीकरण हुआ है वह संचालित हो गये हैं या नहीं? उच्चीकरण स्कूलों में कितने अध्यापक परीक्षण का कार्य कर रहे हैं और उनका वेतन का आहरण कहां से हो रहा है?

शिक्षा

श्री मनोज तिवारी
10.01.2011

33. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा विधान सभा के अन्तर्गत रा0उ0 प्राथमिक विद्यालय धौलनेली, खाटवे, ठौरा, पौमू, चन्द्रकोट, बलमा छतोला हाईस्कूल तक एवं रा0 कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय बल्टा, रा0उ0मा0वि0 (हाईस्कूल), रा0उ0मा0 विद्यालय जसकोट एवं सत्यां इण्टर तक स्कूलों का उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री मनोज तिवारी
10.01.2011

34. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के हाईस्कूल व इण्टर मीडिएट कालेजों के जीर्ण भवनों की मरम्मत पुर्ननिर्माण एवं नये हाईस्कूलों व इण्टरमीडिएट कालेजों के नये भवनों के निर्माण प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

- डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल 35. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 10.01.2011 अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में प्रति विद्यार्थी प्रति माह कितना धन व्यय किया जा रहा है? क्या यह व्यय मानकों से ज्यादा है? शिक्षा
- श्री गोपाल सिंह राणा 36. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2010-2011 में बेसिक 03.02.2011 ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बी०टी०सी०) प्रशिक्षण हेतु प्रदेश सरकार ने कुल कितने प्रशिक्षु चयनित किये हैं तथा वर्तमान में कितने प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण लक्ष्य 4% के अनुसार अनुसूचित जनजाति के कुल कितने प्रशिक्षु चयनित किये गए हैं तथा जनपद वार जनजाति की क्या स्थिति है? क्या सरकार द्वारा प्रदेश स्तर तथा जनपद स्तर पर बी०टी०सी० के प्रशिक्षुओं के आरक्षण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शिक्षा
- श्री तिलक राज बेहड़ 37. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उधमसिंह नगर में जिला शिक्षा 07.02.2011 एवं प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है? क्या संस्थान के लिए नए भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है यदि हाँ, तो भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण होगा? यदि नहीं, तो क्यों? शिक्षा
- हाजी तसलीम अहमद 38. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार जनहित 08.02.2011 में राजकीय कन्या हाईस्कूल, ग्राम निरन्जनपुर, विकास खण्ड लक्सर जिला हरिद्वार का उच्चीकरण हाईस्कूल से इण्टरमीडिएट तक करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? शिक्षा
- हाजी तसलीम अहमद 39. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र— लालढांग 08.02.2011 जिला हरिद्वार में उच्च शिक्षा हेतु कोई भी महाविद्यालय नहीं है? क्या सरकार जनहित में विधानसभा क्षेत्र —लालढांग के किसी ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? उच्च शिक्षा
- श्री जोत सिंह गुनसोला 40. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार द्वारा 09.02.2011 वर्ष 2010-11 हेतु कोई स्थानान्तरण नीति लागू की गई है? यदि हाँ, तो वर्ष 2010-11 में प्राइमरी व जू०हा० के कुल कितने शिक्षकों के स्थानान्तरण किये गये? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि किन-किन महानुभावों की संस्तुति पर उक्त स्थानान्तरण किये गये? क्या सरकार वर्ष 2010-11 में स्थानान्तरित समस्त शिक्षकों की सूची जिलेवार उपलब्ध करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? शिक्षा
- श्री जोत सिंह गुनसोला 41. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि म्यूनिसिपल पी०जी० 09.02.2011 कालेज मसूरी में विषयवार शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत तथा रिक्त हैं? क्या सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा किसी भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा इन रिक्तियों को भरने की कोई कार्यवाही की गई है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाये जाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? उच्च शिक्षा

- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
09.02.2011
42. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैण में रा0प्रा0वि0, रा0मा0वि0, रा0इ0का0 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पदों पर अध्यापक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी हैं? क्या सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- शिक्षा
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
09.02.2011
43. क्या महिला सशक्तिकरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैण विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत व कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कितनी हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण को चुका है और कितने शेष हैं? उक्त केन्द्रों हेतु कितनी धनराशि कब-कब स्वीकृत की गई है?
- महिला
सशक्तिकरण
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
09.02.2011
44. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले के भिक्यासैण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रा0इ0का0 बसेड़ी, मानिला, जनता इ0 कालेज बाजन के भवनों की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हैं, फलस्वरूप कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों के निर्माण के लिये कोई कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?
- शिक्षा
- श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
10.02.2011
45. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी दिशा निर्देशों के बावजूद जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैण ब्लाक समिति की बैठक में दिनांक 28.05.2010 को कितने अधिकारी अनुपस्थित थे? क्या सरकार अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- ग्राम्य विकास
- श्री गगन सिंह रजवार
11.02.2011
46. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड धारचूला एवं मुनस्यारी के राजकीय इण्टर कालेज खेला तथा मवानी-दवानी में इण्टर स्तर पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएँ संचालित की जायेंगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- शिक्षा
- श्री गगन सिंह रजवार
14.02.2011
47. क्या उच्च शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 08.04.2006 को धारचूला जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय महाविद्यालय बलुवाकोट में घोषणा संख्या 108/2006 द्वारा खेल मैदान तथा कक्षों के निर्माण की स्वीकृति की थी? यदि हां, तो क्या सरकार बलुवाकोट महाविद्यालय में खेल मैदान तथा कक्षों का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- उच्च शिक्षा

श्री मयूख महर
06.12.2010

48. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा बी0ए0डी0पी0 योजना हेतु आवंटित धन के कार्यों में निविदा द्वारा कार्य कराये जाने की बाध्यता है? यदि हां, तो मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आर0इ0एस0 पिथौरागढ़ तथा जनपद पिथौरागढ़ के इस योजना के तहत आने वाले विकास खण्ड धारचूला, कनालीछीना, मूनाकोट, मुनस्यारी को वर्ष 2007-2010 तक प्रत्येक को कितनी धनराशि किन-किन कार्यों हेतु उपलब्ध करायी गयी है? उक्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कितने कार्य निविदा से कराये गये हैं व कितने बिना निविदा द्वारा? क्या विभाग केन्द्र के निर्देशों का उल्लंघन करने हेतु इन कार्यदायी संस्थाओं पर कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

ग्राम्य विकास

श्री केदार सिंह रावत
15.02.2011

49. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत भोजन मातायें मानदेय बढ़ाये जाने को लेकर लम्बे समय से आन्दोलनरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनके मानदेय में बढ़ोतरी पर विचार कर रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

श्री केदार सिंह रावत
15.02.2011

50. क्या बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कार्यरत आगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ एवं सहायिकायें मानदेय बढ़ाये जाने को लेकर आन्दोलनरत हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनके मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

बाल विकास एवं
महिला
सशक्तिकरण

श्री केदार सिंह रावत
17.02.2011

51. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि ग्राम्य विकास विभाग में अधिकारी /कर्मचारियों की भारी कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

ग्राम्य विकास

श्री केदार सिंह रावत
18.02.2011

52. क्या बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश सहित उत्तरकाशी जिले में आगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं के चयन हेतु काफी समय पूर्व आवेदन-पत्र मांगे गये थे जिनका परिणाम लम्बित है? यदि हां, तो कब तक परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

बाल विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
18.02.2011

53. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के भिक्यासैण विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने इण्टरमीडिएट कालेज हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि मानकों के अनुसार उक्त कालेजों में कितने प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों के पद सृजित है तथा उसके सापेक्ष किन-किन विद्यालयों में कितने-कितने प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की कमी है? क्या सरकार इन विद्यालयों में प्रवक्ताओं एवं अध्यापकों की कमी को पूर्ण करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा

- श्री दिनेश अग्रवाल
21.02.2011
श्री किशोर उपाध्याय
21.02.2011
54. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "इन्दिरा आवास योजना" प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है?
- ग्राम्य विकास
- श्री दिनेश अग्रवाल
21.02.2011
श्री किशोर उपाध्याय
21.02.2011
55. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना" प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है?
- ग्राम्य विकास
- श्री दिनेश अग्रवाल
22.02.2011
श्री किशोर उपाध्याय
22.02.2011
56. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है तथा प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है?
- ग्राम्य विकास
- श्री दिनेश अग्रवाल
22.02.2011
श्री किशोर उपाध्याय
22.02.2011
57. क्या बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "समग्र बाल विकास सेवा योजना" प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है?
- बाल विकास
- श्री पुष्पेश त्रिपाठी
22.02.2011
58. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा के भवन निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तानान्तरण हो चुका है? यदि हां, तो भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी और कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?
- उच्च शिक्षा
- श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
22.02.2011
59. क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि 18.01.2011 को मुनिकीरेती ऋषिकेश आगमन पर मुख्यमंत्री द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्य का पद डाउन ग्रेड देते हुए शत प्रतिशत पदोन्नति का बनाये जाने हेतु विनियकों में संशोधन किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?
- शिक्षा

- श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
23.02.2011
60. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 06.02.2011 को कोटद्वार आगमन पर मुख्यमंत्री द्वारा राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार में एम0ए0 ड्राईंग व एम0एस0सी0 बायोटेक की कक्षाएँ खोलने की, की गई घोषणा पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
- उच्च शिक्षा
- श्री ओम गोपाल
23.02.2011
61. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत संचालित राजकीय हाईस्कूल रगड़गांव का इन्टर स्तर पर उच्चीकरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?
- शिक्षा
- श्री दिनेश अग्रवाल
25.02.2011
श्री किशोर उपाध्याय
25.02.2011
62. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "सर्व शिक्षा अभियान योजना" प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है तथा प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है?
- शिक्षा
- श्री दिनेश अग्रवाल
25.02.2011
श्री किशोर उपाध्याय
25.02.2011
63. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि "मध्यहन भोजन योजना" प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-2011 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है तथा प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गयी है?
- शिक्षा
- श्री बिशन सिंह चुफाल
25.02.2011
64. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेजों में कुल कितने प्रवक्ताओं के पद रिक्त है तथा कब तक इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी?
- शिक्षा
- श्री बिशन सिंह चुफाल
28.02.2011
65. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत डीडिहाट, धारचूला, मुनस्यारी तथा बेरीनाग चार विकास खण्ड को मिलाकर पी0एम0जी0एस0वाई0 को डिजीजन स्वीकृत है? यदि हां, तो कब से संचालित हो रहा है और किस विकास खण्ड में? यदि नहीं, तो क्यों?
- ग्राम्य विकास
- श्री ओम गोपाल
01.03.2011
66. क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में कुल कितने प्रा0वि0/जू0हा0स्कूल/रा0उ0मा0वि0/इण्टर कालेज है जो कि भवन विहीन/जीर्ण-शीर्ण है? क्या भवन विहीन/जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु सरकार कोई विचार/कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?
- शिक्षा

श्री रणजीत सिंह रावत
01.03.2011

67. क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत शहीद ग्राम मौलेखाल खुमाड़ में स्वीकृत महाविद्यालय में सरकार कब से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उच्च शिक्षा